

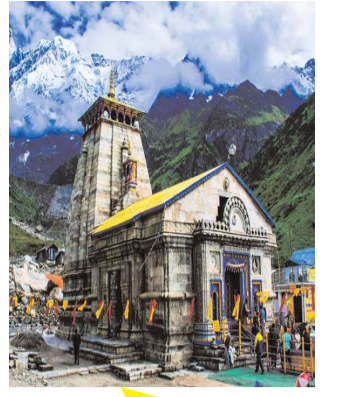


हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

निर्भीक, निष्पक्ष, सच का प्रवाह



वर्ष:5 अंक:149 पृष्ठ:08 मूल्य:1 रूपये

pathpravah.com

हरिद्वार, शुक्रवार, 05 जून 2026

मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की जन कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आई. आर.डी. टी सभागार में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत माह मई 2026 की पेंशन वन क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की। 09 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खाते में कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने नशा मुक्त अभियान एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और देखभाल की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं



का लाभ प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका

प्रयास के मंत्र के साथ देश में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। जन-धन योजना, उज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास

योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। वहीं स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा

योजना, पीएम स्वनिधि, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से वंचित वर्गों को स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिव्यांग कर्मियों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है। स्वयं सहायता समूहों को 'लखपति दीदी योजना' एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना', 'मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना', 'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम' तथा 'अपणि सरकार पोर्टल' के माध्यम से विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व, विभिन्न आयुओं, परिषदों एवं समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद थे।

एक नजर

टीसीएस के बाद विप्रो में धर्मांतरण का आरोप

पीड़ित बोली- कर्मचारी ने इस्लाम अपनाने, मुस्लिम से संबंध बनाने को कहा, शिकायत की तो इस्तीफा लिया

पुणे। पुणे की एक महिला ने विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनी पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के आरोप लगाए हैं। महिला पहले इस कंपनी में काम करती थी। ये आरोप पुणे में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए। इस दौरान पूर्व कर्मचारी ने उन घटनाओं के बारे में बताया, जो उसके साथ उस समय हुई थीं जब वह हिंजवडी ऑफिस में काम करती थीं। इसके बाद पुणे के हिंजवडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पूर्व कर्मचारी के वकील ने बताया कि कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। उन्होंने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है।

पीड़ित महिला ने कहा कि अगस्त 2025 में कंपनी की एक टीम मीटिंग में बुलाया गया था। इस दौरान मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और इस्तीफा ले लिया गया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसकी एक महिला सहकर्मी कई बार उस पर इस्लाम अपनाने और एक मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध बनाने का दबाव डालती थी। उसका कहना है कि सहकर्मी बार-बार उसकी निजी जिंदगी में दखल देती थी और उसे हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहती थी। महिला के अनुसार, सहकर्मी कहती थी कि ऐसा करने से उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और उसे विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। महिला ने आरोप लगाया कि मामले की जानकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय कंपनी की ओम्बड्स कमेटी में उसके खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर दी गई। वहीं, हिंजवडी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।

हॉस्पिटल में आग, 5 की मौत

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों ने मौके से स्टाफ के गायब होने का आरोप लगाया। परिजन अपने मरीजों को स्ट्रेचर से बाहर ले जाते दिखे। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आई। दमकलकर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को खिड़कियों और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। तीन मृतकों की पहचान हो गई है, जिनमें, गीता देवी, चंचला कुमारी, 57 साल के उदय कुमार, 30 साल के शशांक कुमार शामिल हैं। एक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं, हादसे के बाद प्रसाद हॉस्पिटल से कई मरीज गायब बताए जा रहे हैं। इसे लेकर मरीज के परिजन हंगामा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मरीजों को वापस लाया जाए। हालांकि, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उनका दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है।

ओडिशा सीमा पर अभी भी मंडरा रहा नक्सल का खतरा

21 लाख के इनामी 6 नक्सली सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर

भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त घोषित किए जाने के बाद भले ही नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता का दावा किया जा रहा हो, लेकिन ओडिशा की सीमा से सटे इलाकों में खतरा पूरी तरह टला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का कारण दरभा डिवीजन से जुड़े छह ऐसे नक्सली हैं, जो अब भी फरार हैं और जिन पर कुल 21 लाख रुपये का इनाम घोषित है।

इन नक्सलियों की सक्रियता को देखते हुए ओडिशा पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि नक्सली संगठन भले ही कमजोर हुआ हो, लेकिन घने जंगलों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर बचे हुए सदस्य अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं।

मालकानगिरि-कोरापुट के सीमावर्ती क्षेत्र पर विशेष नजर

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दरभा डिवीजन का प्रभाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अलावा ओडिशा के मालकानगिरि जिले के माठिली और कालीमेला ब्लॉक तथा कोरापुट जिले के बैपारिगुड़ा क्षेत्र तक फैला रहा है। एक समय इन इलाकों में नक्सलियों का व्यापक प्रभाव था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में बीएसएफ और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान, आत्मसमर्पण नीति और विकास कार्यों के चलते संगठन को बड़ा झटका लगा है। इसके बावजूद छह नक्सली अब तक सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। इनमें प्लाटून नंबर-26 की पीपीसीएम सदस्य वेद्वी मासे, मालागिरि एरिया कमेटी की एसीएम धनी उर्फ मंगली, एसीएम माडवी नंद कुमार, पार्टी सदस्य हुंगा कुजाम, मासे खुरामी उर्फ क्रांति



तथा पीपीसीएम सदस्य जामली काबासी शामिल हैं। इनमें चार महिला और दो पुरुष नक्सली बताए गए हैं।

जंगलों का सहारा लेकर बचने की कोशिश

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन नक्सलियों की गतिविधियां पहले की तुलना में काफी सीमित हो चुकी हैं। हालांकि ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा के घने जंगल और दुर्गम इलाके अब भी उनके लिए सुरक्षित ठिकाने साबित हो सकते हैं। इसी कारण मालकानगिरि और कोरापुट के सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान जारी हैं। बीएसएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमों लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सल नेटवर्क को लगभग ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन जब तक फरार सदस्यों की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण नहीं होता, तब तक अभियान जारी रहेगा।

आत्मसमर्पण नीति से कमजोर हुआ नेटवर्क

अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति का सकारात्मक असर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है। वहीं कई शीर्ष कमांडर सुरक्षा बलों के अभियानों में मारे

गए हैं। इसके चलते ओडिशा में नक्सली संगठन की ताकत पहले की तुलना में काफी कम हुई है। फिर भी दरभा डिवीजन के इन छह सदस्यों की तलाश सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता बनी हुई है। पुलिस ने इनके बारे में सूचना देने वालों के लिए इनाम की व्यवस्था कर रखी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार खुफिया निगरानी बढ़ाई गई है।

बीएसएफ कैंप हटाने की चर्चा से ग्रामीणों में चिंता

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बीएसएफ जवानों की तैनाती से नक्सली गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण नक्सली खुलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं।

ग्रामीणों का मानना है कि हाल के वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से आम लोगों में भी भरोसा बढ़ा है। हालांकि वर्ष 2027 में कुछ क्षेत्रों से बीएसएफ कैंप हटाए जाने की संभावनाओं को लेकर ग्रामीणों में चिंता दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम हुई तो नक्सली संगठन इसका फायदा उठाकर फिर से अपने नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं।

एक नजर

जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े प्रकरण में एक और गिरफ्तार



पथ प्रवाह, हरिद्वार। जनपद के रुड़की क्षेत्र में भूमि रजिस्ट्री से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जमीन की धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि अपने खाते में लेने के आरोप में वांछित चल रहे आरोपित इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए उसका चालान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, 19 दिसंबर 2024 को सराय ज्वालापुर निवासी संजीव कुमार ने कोतवाली रुड़की में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में रणबीर, इस्लाम तथा अजय उर्फ पिंकू पर भूमि रजिस्ट्री में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र राठी को सौंपी गई थी। जांच के दौरान आरोपित रणबीर पुत्र कंवरपाल निवासी पीतपुरा, थाना लक्सर तथा अजय उर्फ पिंकू पुत्र राजकुमार निवासी पीतपुरा, थाना लक्सर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष वांछित आरोपित की तलाश में गठित पुलिस टीम ने 4 जून को इस्लाम पुत्र अख्तर निवासी मुस्तफाबाद उर्फ पदार्थ, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपित का चालान कर दिया है।

हर की पैड़ी पर खोए बैग और नकदी को पुलिस ने किया बरामद, बहनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान



पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस ने तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर की पैड़ी क्षेत्र से गायब हुए बैग, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर पीड़ित बहनों को सौंप दिए। सामान वापस मिलने पर बहनों ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उसकी कार्यशैली की सराहना की। जानकारी के अनुसार पूजा कुमारी निवासी रोहिणी, नई दिल्ली अपनी चार अन्य बहनों के साथ हरिद्वार घूमने और गंगा स्नान के लिए आई थीं। गुरुवार सुबह हर की पैड़ी क्षेत्र में उनके दो बैग अचानक गायब हो गए। बैग में लगभग 10 हजार रुपये की नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। बैग खो जाने के बाद बहनों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई। उनके पास न तो घर लौटने के लिए पैसे बचे थे और न ही खाने-पीने की व्यवस्था के लिए कोई साधन था। परेशान होकर उन्होंने चौकी हर की पैड़ी पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी हर की पैड़ी में तैनात कांस्टेबल हेमंत और कांस्टेबल नितिन रावत ने तत्काल खोजबीन शुरू की। पुलिसकर्मियों ने क्षेत्र में गहन तलाश अभियान चलाया और कड़ी मशकत के बाद दोनों बैगों को बरामद कर लिया। बैग में रखी पूरी 10 हजार रुपये की नकदी, दस्तावेज और अन्य सामान भी सुरक्षित मिला। पुलिस ने समस्त सामान पूजा कुमारी को सुपुर्द कर दिया। अपना सामान सकुशल वापस मिलने पर पूजा और उनकी बहनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने हरिद्वार पुलिस की तत्परता, ईमानदारी और जनसेवा भाव की प्रशंसा करते हुए पुलिस टीम का धन्यवाद किया।

हरिद्वार के घरों में स्मार्ट मीटर की तैयारी, पुलिस-प्रशासन से मांगा सहयोग

पथ प्रवाह, हरिद्वार। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी रीवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत जनपद हरिद्वार में स्मार्ट मीटर स्थापना का कार्य शुरू किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता (वितरण) शेखर चंद्र ने बताया कि यह कार्य जयपुर की कंपनी मैसर्स जीनस पावर सॉल्यूशन प्रा. लि. द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पारदर्शी बिलिंग, बिजली खपत की सटीक जानकारी, रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत सरकार के 1 अप्रैल 2026 के राजपत्र के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी विद्युत उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। जनपद में स्मार्ट मीटर स्थापना का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में हरिद्वार और रुड़की विद्युत वितरण मंडलों के विभिन्न क्षेत्रों में 6 से 20 जून तक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हरिद्वार मंडल में जगजीतपुर, सराय, इब्राहिमपुर खुर्द, इब्राहिमपुर कला, शिवालिक नगर, मायापुर, भूपतवाला और कनखल क्षेत्र शामिल हैं, जबकि रुड़की मंडल में सोत मोहल्ला, बीएसएम तिराहा, आवास विकास, लेबर चौक, डिफेंस कॉलोनी, सिविल लाइंस, आदर्श नगर, इंदगाह रोड और रामपुर तिराहा क्षेत्रों में यह कार्य किया जाएगा। स्मार्ट मीटर स्थापना को लेकर कुछ स्थानों पर संभावित विरोध की आशंका को देखते हुए कार्य के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक सहयोग की मांग की गई है।

भीमगोड़ा-खड़खड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा, व्यापारियों के विरोध के बाद रुका अभियान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

आगामी कुम्भ एवं सावन मेले की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासन द्वारा हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भीमगोड़ा और खड़खड़ी क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान भीमगोड़ा स्थित रेलवे बाउंड्री के अंदर बने अवैध टिनशेड, तिरपाल और खोखा-पटरी की दुकानों को हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई में करीब 40 से 50 अस्थायी खोखे ध्वस्त किए गए। इस दौरान अपनी तिरपाल हटाने का प्रयास कर रहा एक व्यक्ति छप्पर से नीचे गिरकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भेजा गया।

कार्रवाई के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब जेसीबी मशीन सुविधा होटल क्षेत्र में पहुंची। यहां स्थायी दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। वहीं खोखा-पटरी दुकानदारों ने भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप था कि रेलवे भूमि पर बने उनके खोखों को हटाया जा रहा है, जबकि नालों पर किए गए स्थायी



अतिक्रमण के खिलाफ समान कार्रवाई नहीं की जा रही है।

स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद प्रशासन की टीम पंजाब सिंध क्षेत्र पहुंची, जहां अमृतसरी वैष्णव ढाबा और शिव भोजनालय के ऊपर लगे बोर्डों को भी हटाया गया। इस कार्रवाई का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया और कई दुकानदार जेसीबी मशीन के आगे

लेट गए। बढ़ते विरोध के बीच सहायक नगर आयुक्त (एसएनए) महेंद्र यादव, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष संजीव नैयर तथा स्थानीय व्यापारियों के बीच वार्ता हुई। बातचीत के बाद सहमति बनने पर प्रशासन ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी। मौके पर तरुण नैयर, अजय अरोड़ा, निक्की, अनुज गुप्ता, बलकेश राजोरिया, गौरव सचदेव, वैभव सुखिजा, अंकन जैन, पंकज सुखीजा सहित सैकड़ों व्यापारी और दुकानदार मौजूद रहे।

भीमगोड़ा-खड़खड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा, व्यापारियों के विरोध के बाद रुका अभियान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

आगामी कुम्भ एवं सावन मेले की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासन द्वारा हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भीमगोड़ा और खड़खड़ी क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान भीमगोड़ा स्थित रेलवे बाउंड्री के अंदर बने अवैध टिनशेड, तिरपाल और खोखा-पटरी की दुकानों को हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई में करीब 40 से 50 अस्थायी खोखे ध्वस्त किए गए। इस दौरान अपनी तिरपाल हटाने का प्रयास कर रहा एक व्यक्ति छप्पर से नीचे गिरकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भेजा गया।

कार्रवाई के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब जेसीबी मशीन सुविधा होटल क्षेत्र में पहुंची। यहां स्थायी दुकानदारों ने



कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। वहीं खोखा-पटरी दुकानदारों ने भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप था कि रेलवे भूमि पर बने उनके खोखों को हटाया जा रहा है, जबकि नालों पर किए गए स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ समान कार्रवाई नहीं की जा रही है।

स्थिति को देखते हुए पुलिस और

प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद प्रशासन की टीम पंजाब सिंध क्षेत्र पहुंची, जहां अमृतसरी वैष्णव ढाबा और शिव भोजनालय के ऊपर लगे बोर्डों को भी हटाया गया। इस कार्रवाई का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया और कई दुकानदार जेसीबी मशीन के आगे

लेट गए। बढ़ते विरोध के बीच सहायक नगर आयुक्त (एसएनए) महेंद्र यादव, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष संजीव नैयर तथा स्थानीय व्यापारियों के बीच वार्ता हुई। बातचीत के बाद सहमति बनने पर प्रशासन ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी।

मौके पर तरुण नैयर, अजय अरोड़ा, निक्की, अनुज गुप्ता, बलकेश राजोरिया, गौरव सचदेव, वैभव सुखिजा, अंकन जैन, पंकज सुखीजा सहित सैकड़ों व्यापारी और दुकानदार मौजूद रहे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान, दो आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मारपीट के वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार 3 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक युवक के हाथ बांधकर उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर मुकदमा दर्ज किया और संबंधित आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी रोड़ीबेलवाला क्षेत्र स्थित एक पार्किंग में कार्यरत थे। किसी विवाद के चलते उन्होंने



युवक के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस ने यह भी पाया कि पार्किंग संचालक द्वारा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था। इस पर पार्किंग मालिक के खिलाफ भी पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नूतन पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम

बिलाई, थाना हलदौर, जनपद बिजनौर (उत्तर प्रदेश) तथा रोबिन पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम मुडदाना, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है।

हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली घटनाओं पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।

समीक्षा अधिकारी की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न

पथ प्रवाह, हरिद्वार। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रशान्त ने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय की समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2024 की टंकण परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2024 के अंतिम हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा का आयोजन दिनांक 04 जून, 2026

(बृहस्पतिवार) को एकल परीक्षा केन्द्र ज्ञानोदय कम्प्यूटर लैब, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार (केन्द्र कोड-101) में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा: पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रारम्भ कुल पंजीकृत अभ्यर्थी: 15, उपस्थित अभ्यर्थी: 12, अनुपस्थित अभ्यर्थी: 03, उपस्थिति प्रतिशत: 80% कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण परीक्षा: मध्याह्न 12:00 बजे से प्रारम्भ

कुल पंजीकृत अभ्यर्थी: 15, उपस्थित अभ्यर्थी: 12, अनुपस्थित अभ्यर्थी: 03, उपस्थिति प्रतिशत: 80%, परीक्षा केन्द्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं तथा परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रशान्त ने अवगत कराया कि परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराई गई है।



हरिद्वार में अतिक्रमण पर प्रशासन का जबरदस्त प्रहार, 100 से अधिक अवैध कब्जे हटाए

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेले को सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, फुटपाथ, नालियों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित और सुचारु यातायात व्यवस्था के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपदभर में अतिक्रमण हटाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, नगर निकायों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि, सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी के नेतृत्व में वाल्मीकि चौक (ललतारी पुल) से अपर रोड



तक तथा उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा के नेतृत्व में भीमगोड़ा बैरियर से जयराम आश्रम होते हुए सुखी नदी तक नगर निगम, पुलिस, जिला प्रशासन, एसएसबी और सेना की निगरानी में अभियान चलाया गया। इस दौरान नालियों और फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए तथा नालियों के ऊपर बने खोखों और ढाबों को ध्वस्त किया गया।

प्रशासन के अनुसार दोनों टीमों ने मिलकर 100 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण हटाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी व्यक्ति द्वारा नालियों या सार्वजनिक मार्गों पर सामान, निर्माण सामग्री अथवा व्यावसायिक सामग्री रखी गई तो उसे तत्काल जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बार-बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ

कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

अभियान के दौरान सिटी उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, उप नगर आयुक्त महेंद्र यादव, सफाई निरीक्षक धीरेन्द्र सेमवाल, श्रीकांत, मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा, मनोज कुमार, हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी, एसएसआई गोपाल दत्त भट्ट सहित नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

मंगलौर में 10 किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई

संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के अनुसार मंगलौर क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर दायरे में सड़क, नालों, फुटपाथों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित रेहड़ी, ठेली और खोखे भी हटाए गए। प्रशासन ने बताया कि यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा।

सुल्तानपुर बाजार में 50 से अधिक अतिक्रमण हटें

लक्कर के सुल्तानपुर बाजार क्षेत्र में उप

जिलाधिकारी अनिल शुक्ला के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान सड़क किनारे, फुटपाथ और नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। अभियान में 50 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए तथा 16 लोगों के चालान भी किए गए। इस दौरान तहसीलदार दीवान सिंह राणा सहित प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।

भगवानपुर में गागलहेड़ी रोड पर चला अभियान

भगवानपुर तहसील क्षेत्र में तहसीलदार दयाराम के नेतृत्व में गागलहेड़ी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क, नालियों और फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए तथा लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गई। प्रशासन का कहना है कि चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

एक नजर

सीवरेज के लिए खोदी गई सड़कों को तेजी से किया जा रहा ठीक



पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार शहर के अंतर्गत सीवरेज कार्य हेतु खोदी गई सड़कों से क्षेत्रीय जनता, व्यापारियों को हो रही परेशानी के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से दिन रात कार्य करते हुए पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कांटेक्टर को दिए गए हैं। परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम मिनाक्षी मित्तल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में केएफडब्ल्यू वित्त पोषित हरिद्वार जलोत्सर्गण योजना पैकेज 01 एवं पैकेज 02 के अंतर्गत कराए जा रहे सड़क पुनर्निर्माण संबंधी कार्य जिसके तहत 04 जून को किए गए निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत है जिसमें- पैकेज 01 के अंतर्गत राणा रोड सीसी 47.7 रोड मीटर, लोधा मंडी सीसी रोड 20 मीटर, प्रेम विहार चौक सीसी रोड 45.6 मीटर, गायत्री तपोवन सीसी रोड 30 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कुल 143.3 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पैकेज 02 के अंतर्गत गणपतिधाम फेस 2 पावर ब्लॉक 15 मीटर, गणपतिधाम फेस 3 पावर ब्लॉक 60 मीटर, मोहन इंकलेव सीसी रोड 35 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुल 110 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सड़कों का कार्य दिन-रात त्वरित गति से किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया स्वामी

कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डा.स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नई दिल्ली में हुई भेंट के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के संबंध में स्वामी कैलाशानंद गिरी से विस्तार से चर्चा की। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि कुंभ धर्म, संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। उन्होंने कहा कि सभी तरह अखाड़े मिलकर सिंहस्थ महाकुंभ को सनातन की गरिमा के अनुरूप दिव्य और भव्य स्वरूप में संपन्न कराएंगे। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को अगले वर्ष हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में शामिल होने का निमंत्रण दिया और कहा कि हरिद्वार कुंभ की दिव्य छ्त्रा पूरे विश्व को आलोकित करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि संत महापुरुषों का सानिध्य सौभाग्य से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और संत महापुरुषों के आशीर्वाद से सिंहस्थ महाकुंभ को गरिमा और दिव्यता के साथ भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। सिंहस्थ कुंभ मे शाही स्नान और आध्यात्मिक आयोजनों के दौरान संतों एवं श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर दिए गए हैं। इस दौरान स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिष्य स्वामी अर्वाकानंद ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे।



एचआरडीए सचिव मनीष सिंह को महाप्रबंधक कुमाऊं मंडल विकास निगम नई जिम्मेदारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सचिव मनीष सिंह को उनके वर्तमान पद से पदमुक्त कर दिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब वह अपनी मूल तैनाती के तहत सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल तथा महाप्रबंधक कुमाऊं मंडल विकास निगम के पद का अतिरिक्त दायित्व संभालेंगे। उनके स्थानांतरण के बाद एचआरडीए में सचिव का पद फिलहाल रिक्त हो गया है, जिससे नए सचिव की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मनीष सिंह ने एचआरडीए सचिव के रूप में लंबे समय तक कार्य करते हुए प्राधिकरण की विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



उनके कार्यकाल में अवैध निर्माणों और मानचित्र स्वीकृति के बिना किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ कई प्रभावी अभियान चलाए गए। इसके साथ ही शहरी विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और नियोजित विकास की दिशा में भी अनेक

कदम उठाए गए। मनीष सिंह इससे पूर्व डिप्टी कलेक्टर और उपजिलाधिकारी (एसडीएम) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके पदमुक्त होने के बाद हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में नए सचिव की नियुक्ति को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों के अनुसार कई वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों के नाम इस पद के लिए चर्चा में हैं। हालांकि शासन की ओर से अभी तक किसी अधिकारी की नियुक्ति संबंधी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अब सभी की निगाहें शासन के अगले फैसले पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही शासन इस महत्वपूर्ण पद पर किसी सक्षम अधिकारी की तैनाती कर सकता है, जिससे प्राधिकरण के विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और लंबित योजनाओं को गति मिल सके।

इण्डोनेशिया में नवाचार के माध्यम से योग, आयुर्वेद, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, अनुसंधान को उन्नत बनाने का कार्य करेगा पतंजलि: आचार्य बालकृष्ण

पथ प्रवाह, हरिद्वार/इण्डोनेशिया।

पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण इण्डोनेशिया प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के दौरान आचार्य बाली प्रांत पहुंचे और बाली प्रांत के विधानसभा अध्यक्ष Mr Dewa Made Mahayadnya तथा बाली के एम.एल.ए. डॉ. सोमवीर से भेंटवार्ता की। इससे पूर्व बाली प्रांत के चेयरमैन ने आचार्य का सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण स्वागत किया। उन्होंने आचार्य जी को बतौर राजकीय अतिथि के रूप में आतिथ्य प्रदान करते हुए हर्बल उद्यान भ्रमण की सारी व्यवस्था की थी।

भेंटवार्ता के दौरान Mr Dewa Made Mahayadnya ने कहा कि पतंजलि योगपीठ का विकास मॉडल आज पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। पतंजलि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान आदि विविध क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने आचार्य जी से बाली में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि के क्षेत्र में पतंजलि के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर आचार्य जी ने सहर्ष



सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द साझा प्रयासों से हम बड़ा कार्य करेंगे। उन्होंने पतंजलि के गुणवत्तायुक्त उत्पादों की प्रशंसा की तथा बहुत जल्द भारत आने की इच्छा प्रकट की।

इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि के सेवा कार्य आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल हैं। जल्द ही हम इण्डोनेशिया

में अपने सेवाकार्यों का विस्तार करेंगे जिसका लाभ यहाँ के आमजन को मिलेगा। योग, आयुर्वेद, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, अनुसंधान को इण्डोनेशिया में नवाचार के माध्यम से उन्नत बनाने का कार्य पतंजलि योगपीठ करेगा जिससे इण्डोनेशिया के युवाओं को रोजगार भी सुलभ होगा। इस अवसर पर आचार्य जी ने हर्बल उद्यान का भ्रमण भी किया।

पुलिस परिवार के बेटे की सफलता बनी प्रेरणा, एसएसपी नवनीत सिंह ने दी बधाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मेहनत अगर सच्चे जज्बे के साथ की जाए तो सफलता दरवाजे पर दस्तक दे ही देती है। इस बात का ताजा उदाहरण कोतवाली ज्वालपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर रणवीर चंद रमोला के सुपुत्र को मिली सफलता है। रमोला के बेटे मनीष रमोला ने UKPCS परीक्षा 2026 में सफलता का झंडा गाड़ते हुए तीसरा



स्थान हासिल किया। उनका चयन डिप्टी एसपी रैंक के लिए हुआ है। कप्तान नवनीत सिंह द्वारा कैप कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार में भेंट के दौरान पिता-पुत्र को बधाई देते हुए सम्मानित किया गया तथा मिठाई खिलाकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। एसएसपी नवनीत सिंह द्वारा इस सफलता को पुलिस विभाग के सभी सदस्यों और उनके परिजनों के लिए प्रेरणा बताया।



संपादकीय

हाका लगाकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शिकार

जब किसी का शिकार करना होता है तो शिकारी शिकार को हाका लगाकर ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पहले से ही कोई बड़ा गड़गड़ा खुदा होता है। चबराहट में शिकार भागता हुआ जाता है और उसी गड़गड़े में गिर जाता है। उसके बाद शिकार को पिंजरे में बंद करके रख लिया जाता है। कुछ इसी तरह का शिकार पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ममता बनर्जी की टीएमसी का किया है। ममता बनर्जी की 28 साल पुरानी पार्टी का शिकार परंपरागत तरीके से कर लिया है। पार्टी के 58 विधायकों को ममता बनर्जी से दूर करने का जो जाल फैलाया गया था, उसी जाल में ममता फंस चुकी हैं। इस जाल को तोड़कर बाहर निकलना शायद ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए अब संभव नहीं रहा। विधानसभा के चुनाव में जैसे-तैसे 80 सीटों पर टीएमसी के विधायक जीते थे। टीएमसी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र बोस को पत्र भेजा गया था, जिसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय को टीएमसी के विधायक दल का नेता और सचेतक इत्यादि की जानकारी दी गई थी। नामों वाला संबंधित पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजकर नियुक्ति का अनुरोध किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसी बीच ऋतुवत बनर्जी ने जो टीएमसी के विधायक हैं और उनके एक साथी विधायक ने अपने हस्ताक्षर जाली बताकर विधानसभा अध्यक्ष के यहां आपत्ति जताई। मामला पुलिस और सीआईडी तक पहुंचा। टीएमसी के पत्र पर नियुक्ति रोक दी गई। उसके बाद ऋतुवत बनर्जी को भाजपा और विधानसभा अध्यक्ष का संरक्षण मिला। एक सूची 58 विधायकों की ऋतुवत बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी। विधानसभा अध्यक्ष ने ताबड़तोड़ ऋतुवत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। उन्होंने सचेतक के रूप में जो नाम दिया था उसे स्वीकार कर लिया। जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निश्चित रूप से संसदीय परंपराओं में जिस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिए थी वह नहीं की गई। जिस तरह से सांसद अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी की सड़क पर पिटाई की गई थी, उसके वीडियो वायरल किए गए, विधायकों को बैठक में नहीं पहुंचने दिया गया। विधायकों के बीच यह संदेश पहुंचाया गया वह ममता बनर्जी का साथ छोड़ दें और ऋतुवत बनर्जी के साथ आ जाएं। तभी वह सुरक्षित रहेंगे अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

अभिषेक बनर्जी के घर ईंड़ी ने दस्तक दे दी है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार टीएमसी के विधायकों और नेताओं के ऊपर कार्यवाही कर रही है, 2 लाख से अधिक केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। हाईकोर्ट और विधानसभा अध्यक्ष से भी कोई सहायता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मिलती हुई दिख नहीं रही है। ऐसी स्थिति में टीएमसी के विधायकों में भगदड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। उनके सामने दो ही विकल्प हैं यदि वह सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ममता बनर्जी को छोड़कर ऋतुवत बनर्जी के साथ आ जाएं अन्यथा उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चलेंगे और सड़क में उनके ऊपर हमले भी हो सकते हैं। अभी तक अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे ताकतवर नेताओं के ऊपर जो हमले हुए हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से टीएमसी में भय का वातावरण बन गया है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है कुछ इसी तरह से महाराष्ट्र में भी हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। समय निकल जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्यपाल ने जो फैसला लिया था वह गलत था। असंवैधानिक रूप से महाराष्ट्र की सरकार बनी। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया वह बगावती विधायकों के पक्ष में था। कुल मिलाकर समय निकलता चला गया और समय पर कोई निर्णय किसी भी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं दिया गया। जिसके कारण अवैध रूप से बनी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। कुछ इसी तरह की स्थिति अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के ऊपर हाका लगाया जा रहा है। जिस तरह की स्थितियां अभी देश में बनी हुई हैं पश्चिम बंगाल की सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट से कोई राहत ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं को मिलेगी यह दिखता नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब संविधान और लोकतंत्र की बात करना एक तरह से बेमानी हो गया है।

प्रकृति से संगति, भविष्य से दोस्ती: सिर्फ एक दिन क्यों?

सुनील कुमार महला

नीला ग्रह यानी कि यह पृथ्वी हमारा इकलौता घर है और इसकी सुरक्षा तथा संरक्षण किसी एक व्यक्ति, देश या संस्था की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यही संदेश प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस देता है। यदि इस दिवस को मनाने के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें, तो इनमें प्रदूषण, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के ह्रास जैसे गंभीर मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना; सरकारों, उद्योगों और आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना; विकास के साथ सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा देना; तथा हर परिस्थिति में पृथ्वी के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करना शामिल है।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2025 की थीम प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की पुनर्कल्पना रखी गई थी। दरअसल, यह थीम इस बात पर केंद्रित थी कि जिस प्रकार मानव प्रकृति का निरंतर दोहन कर रहा है, उसे बदलकर अधिक संतुलित और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वहीं वर्ष 2026 की थीम प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए। निर्धारित की गई है। इस वर्ष का प्रमुख अभियान सनाऊ फोर क्लाइमेट है, जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर बल देता है। साथ

ही वर्ष 2026 के वैश्विक आयोजन की मेजबानी अजरबैजान को सौंपी गई है। हाल फिलहाल, यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास पर दृष्टि डालें, तो पाठकों को बताता चलू कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी नींव रखी थी। यही वह अवसर था जब विश्व के देशों ने पहली बार पर्यावरण और मानव जीवन के पारस्परिक संबंधों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया। आधिकारिक रूप से पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसका मुख्य नारा (स्लोगन) केवल एक पृथ्वी था। वास्तव में इस दिवस को मनाने का महत्व आज और अधिक बढ़ गया है। वैज्ञानिक चेतानियों के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान खतरनाक स्तर अर्थात् 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के निकट पहुंच रहा है। ऐसे में यह दिवस जलवायु संकट के प्रति दुनिया को सचेत करने वाले एक वैश्विक अलार्म की तरह कार्य करता है। वर्तमान में 150 से अधिक देश और करोड़ों लोग इस अभियान (पर्यावरण संरक्षण) से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में भाग लेते हैं। आज इस दिवस पर ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग जैसे आधुनिक विषयों पर भी चर्चा की जा रही है।

स्पष्ट है कि अब दुनिया का ध्यान ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

ललित गर्ग

5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य को बचाने का वैश्विक संकल्प है। वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के अस्तित्व को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। इस वर्ष की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' (ठमंज च्सेंजपब च्वससनजपवद) केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान नहीं है, बल्कि उपभोगवादी जीवनशैली और प्रकृति-विरोधी विकास मॉडल पर पुनर्विचार का भी संदेश है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी जीवन को असहनीय बना रही है, कहीं अनियंत्रित वर्षा और बाढ़ तबाही ला रही है, तो कहीं सूखा और जल संकट मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में आग, हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, महानगरों में प्रदूषण, बेंगलुरु जैसे तकनीकी नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि पिछले एक दशक में जलवायु संबंधी आपदाओं से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और खरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण-ये तीनों संकट परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव सभ्यता के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आज भी

वृक्षों को राखी बांधकर की पहाड़ की तीरांगनाओं ने पर्यावरण की रक्षा!

डॉ श्रीगोपाल नारसन

प्राकृतिक धरोहर में समृद्ध उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए उत्तराखंड के लोग सदा आगे रहे हैं। हरिद्वार वृक्षों को पैसो के लालच में काटने वाले वन माफियाओं से टकराने में यहां संघर्षरत रहे लोगो ने कभी अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी वृक्षों को राखी बांधकर और वर्षों पर आरी और कुल्हाड़ी चलने के समय वृक्षों से चिपकर कर वृक्षों को काटने से बचाया है। उत्तराखंड में कुछ लोगो ने जूनून की हद तक पर्यावरण बचाने के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षशील विभूतियों में चाहे सुंदर लाल बहुगुणा हो या फिर विश्वेश्वर दत्त सकलानी अथवा गौरा देवी जिन्हें आज भी उत्तराखण्ड में पर्यावरण का मसीहा कहा जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जीवन पर्यन्त उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव टिहरी के पुजारा में रहे। उनमें वृक्ष लगाने की धुन सवार थी। लगता था जैसे वृक्ष ही उनका परिवार हो। तभी तो उनके जाने के बाद से इंसान ही नहीं वे पेड़ पौधे भी आज तक गमजदा है, जिनके लिए सकलानी जीवन पर्यन्त जीते रहे। क्या कोई इंसान कभी वृक्ष व वनसम्पदा से इतना लगाव और प्यार कर सकता है जितना सकलानी ने कर दिखाया। वह एक ऐसा हरियाली का नायक था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धरती मां को हरा भरा रखने के लिए समर्पित कर दिया। वह एक ऐसा तपस्वी था जिसकी मेहनत गढ़वाल की एक पूरी घाटी को हरियाली में बदल चुकी है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वनत्रिषि भी कहा जाता था। उन्होंने मात्र 8 साल की उम्र से पेड़ लगाने शुरू किए थे और जीवन के अंत तक 50 लाख से अधिक पेड़ लगाकर दुनिया को पर्यावरण के प्रति एक रिकार्डमय संदेश दिया। इन्हें पहाड़ का मांझी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसने अपनी मेहनत से विशाल जंगल तैयार कर दिया है। जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने को खुशहाल महसूस करेंगी।

विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने अपनी उम्र के

दुनिया उस दिशा में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विश्व के सामने उपस्थित इस सबसे बड़े संकट को भारत की राजनीति में वह महत्व नहीं मिला, जिसका वह अधिकारी है। चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरण का उल्लेख तो होता है, लेकिन वह केवल औपचारिकता भर रह जाता है। राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन वोट दिलाने वाले मुद्दे नहीं हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रश्न न तो चुनावी बहस का हिस्सा बनते हैं और न ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का। जबकि सच्चाई यह है कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसी प्रश्न पर निर्भर करती है।

पर्यावरणीय संकट का मूल कारण विकास की वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन और उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। हमने जंगलों को उद्योगों के लिए, नदियों को अपशिष्ट के लिए और भूमि को कंक्रीट के जंगलों में बदलने के लिए प्रयोग किया। प्रकृति हमें जीवन का आधार निःशुल्क देती है, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञता के बजाय दोहन का व्यवहार अपनाया। परिणामस्वरूप वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का संकट, भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति को पूजनीय माना है। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और वनस्पतियों को केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में देखा गया। आयुर्वेद और वनौषधि विज्ञान इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों ने हजारों वर्षों तक मानव स्वास्थ्य की रक्षा की, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह ज्ञान और प्राकृतिक संपदा दोनों उपेक्षित होते गए। आज जब नई-नई बीमारियां मानव जीवन को चुनौती दे रही हैं, तब पुनः प्रकृति और वनस्पति जगत की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की

असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि 'गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है।' आज यह कथन और अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि गरीबी और पर्यावरणीय विनाश एक-दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बन गए हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों की कमी नहीं है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से लेकर अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए गए। लेकिन कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई बनी हुई है। अवैध खनन, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनदेखी और पर्यावरणीय मंजूरीयों में शिथिलता इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थागत इच्छाशक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है।

फिर भी आशा की किरण दिखाई देती है। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में युवाओं ने जलवायु संकट को गंभीर विषय माना है और सरकार से इस संबंध में शिक्षा एवं जनजागरण की अपेक्षा की है। यह संकेत है कि नई पीढ़ी पर्यावरण को केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि अपने भविष्य का प्रश्न मान रही है। आवश्यकता इस चेतना को सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदलने की है। समाधान क्या है? सबसे पहले विकास और पर्यावरण को विरोधी नहीं, पूरक मानने की दृष्टि विकसित करनी होगी।

ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, जल संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान बनाना, वृक्षरोपण को जनांदोलन का रूप देना और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। केवल सरकारी योजनाओं से यह कार्य संभव नहीं होगा, इसके लिए समाज, उद्योग, शिक्षा संस्थानों और नागरिकों की साझी भागीदारी चाहिए।

अंतिम पड़ाव में भी आंखों की रोशनी चली जाने के बावजूद पेड़ लगाना जारी रखा। पेड़ के पुजारी विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म 2 जून 1922 को हुआ था।

बचपन से विश्वेश्वर दत्त को पेड़ लगाने का शौक था और वे अपने दादा के साथ जंगलों में पेड़ लगाने जाते रहते थे। उनका जीवन माउन्टेन मैन दशरथ मांझी की तरह रहा है, जिन्होंने एक सड़क के लिए पूरा पहाड़ खोद दिया था। दशरथ मांझी की तरह विश्वेश्वर दत्त सकलानी के जिनंदगी में भी अहम बदलाव तब आया जब उनकी पत्नी शारदा देवी का देहांत सन 1948 को हो गया। इस घटना के बाद उनका लगाव वृक्षों और जंगलों की तरफ हो गया। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य बन गया था केवल वृक्षरोपण करना और उन्हीं के लिए जीना। सकलानी ने धरती मां के लिए अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। बीमारी के बावजूद जंगलों में पेड़ लगाने का उनका जूनून कम नहीं हुआ। जब शरीर ने भी साथ छोड़ दिया तब भी वे पेड़ के लिए ही सांस लेते रहे। तभी तो उन्हें वृक्षमानव की उपाधि से नवाजा गया। विश्वेश्वर दत्त सकलानी अंत तक अपने पैतृक गांव पुजारा में रहते रहे। उनकी सांसे भी पेड़ों की ही बातें करती रही। विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने उत्तराखंड की सकलानी घाटी की तस्वीर ही बदल कर रख दी। करीब 60-70 साल पहले तक इस पूरे इलाके में अधिकतर इलाका पेड़ विहीन था। सकलानी ने धीरे धीरे बांज, बुरांश, सेमल, भीमल और देवदार के पेड़ लगाने शुरू किये। शुरू शुरू में ग्रामीणों ने इसका काफी विरोध किया, यहां तक कि उनपर कई बार हमला भी किया गया, लेकिन धरती मां के इस नायक ने अपना जूनून नहीं छोड़ा जिसके परिणाम स्वरूप करीब 1200 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में उनके द्वारा पूरा जंगल खड़ा हो चुका है। पुजारा गांव के लोग बताते हैं कि जब उनकी बेटी का विवाह हुआ और कन्यादान होने जा रहा था तो उस समय में वह जंगल में वृक्षरोपण करने गए हुए थे।

विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जीवन उन पर्यावरण विदों के लिए आईना है जो अपने जुगाड़ के कारण बड़े बड़े अवार्ड हथिया लेते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही सुन्दरलाल बहुगुणा को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण विद के रूप में जाना जाता है। सुंदर लाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) के मरोड़ा गाँव में हुआ था। उनकी पहचान चिपको आंदोलन के अगुआ के रूप में भी की जाती है। उन्होंने सन 1970 के दशक में हिमालय के जंगलों को बचाने के लिये कई वर्षों तक संघर्ष किया। सुंदर लाल बहुगुणा जी आम जन को जागरूक करने और अपने आंदोलन में सहयोग की मांग को लेकर वर्ष 1981 से 1983 के दौरान हिमालय क्षेत्र में 5000 किमी की पैदल यात्रा की। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके अतुलनीय योगदान के लिये भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे जीवन पर्यंत पर्यावरण के प्रति समर्पित रहे। महिला शक्ति की प्रतीक

गौरा देवी सन 1925 में जन्मी थी, वह चिपको आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी गई। उनके मन में बचपन के दिनों में माँ से पर्यावरण को संजोने की प्रेरणा पैदा हुई। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रेनी नामक छोटे से गाँव में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं का एक समूह तीन दिन व तीन रात जंगल में पेड़ों से चिपककर खड़ा रहा और इस प्रतिरोध के द्वारा पेड़ों को काटने से रोका। उस समय गाँव के पुरुष काम करने के लिए चमोली गये हुये थे, इसी बात का फायदा उठाकर वन माफियाओं द्वारा पेड़ों को काटने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन गौरा देवी ने वन माफियाओं के इरादे पर पानी फेर दिया। उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुये उनसे कहा कि हमने इन पेड़ों को गले लगाया है। अगर वे इन पेड़ों को काटना चाहते हैं तो पहले कुल्हाड़ी उनके शरीर पर चलाओ। यह सुनकर पेड़ काटने आए लोग पीछे हट गये और गौरा देवी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।

एक नजर

मुख्यमंत्री आवास परिसर में थी-बी गार्डन के निर्माण कार्य का कृष्णा वट के पौधे से शुभारम्भ



पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित राजकीय उद्यान, सकिट हाउस देहरादून में विकसित किए जा रहे 3-बी गार्डन (बी-फ्रेंडली, बटरफ्लाई-फ्रेंडली एवं बर्ड-फ्रेंडली गार्डन) के निर्माण कार्य का शुभारम्भ कृष्णा वट के पौधे का रोपण कर किया गया। इस उद्यान का विकास मधुमक्खियों, तितलियों एवं पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परागण एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का व्यापक स्तर पर रोपण किया जा रहा है। उद्यान के आसपास कीटनाशकों एवं अन्य हानिकारक रसायनों के उपयोग को प्रतिबंधित रखा जाएगा, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके।

इस विशेष उद्यान के निर्माण से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा। साथ ही आमजन में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी यह उद्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित को इस प्रकार के उद्यान के विकास करने के निर्देश दिये गए थे। तत्पश्चात उपयुक्त प्रजातियों के पौधों के चयन एवं रोपण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। उद्यान में जामुन, शहतूत, सहजन, कदम्ब, कपूर, गुड़हल, अमरूद, नीम, बाँस, बॉटल ब्रश, टिकामा, जीनिया, कॉसमॉस, पेटास, मिल्कवीड, पैशन फ्लावर, हमेलिया, इक्जोरा, लैंटाना, तुलसी, लैवेंडर, सूरजमुखी, रोजमरी एवं पुदीना सहित अनेक प्रजातियों के पौधों का मिश्रित रूप से रोपण किया जा रहा है। परिसर में स्थित जीर्ण-शीर्ण एवं वृद्ध वृक्षों के समीप नवीन पौधों के रोपण का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च हिमालयी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बाँज, बुरांश, तेजपत्ता तथा पया प्रजाति के पौधों का रोपण भी विगत वर्ष से किया जा रहा है, जो वर्तमान में स्वस्थ वृद्धि के साथ परिसर की प्राकृतिक शोभा एवं विशिष्टता को बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने परिसर में संचालित पर्यावरणीय एवं जैव विविधता संवर्धन संबंधी कार्यों की सराहना करते हुए उद्यान विभाग को मधुमक्खी पालन गतिविधियों को मुख्यमंत्री आवास परिसर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर विकसित करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, निदेशक उद्यान डॉ. आर.के. सिंह, नरेन्द्र यादव मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने टिहरी गढ़वाल में बजरंग सेतु एवं हिलान्स हिमालयन भोजनालय का किया निरीक्षण



पथ प्रवाह, टिहरी गढ़वाल। मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन आनंद बर्धन द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रांतर्गत तपोवन स्थित बजरंग सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ओम प्रकाश द्वारा सेतु की इंजीनियरिंग संरचना, तकनीकी विशेषताओं एवं निर्माण संबंधी पहलुओं की विस्तृत जानकारी मुख्य सचिव को प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति एवं सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

तत्पश्चात मुख्य सचिव द्वारा नरेंद्रनगर विकासखंड अंतर्गत प्लास्टा स्थित हिलान्स हिमालयन भोजनालय का निरीक्षण किया गया। हिलान्स हिमालयन भोजनालय की संचालक बीना पुंडीर द्वारा भोजनालय में प्रतिदिन आने वाले ग्राहकों एवं दैनिक बिक्री से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही रीप परियोजना से छह लाख, बैंक लोन तीन लाख एवं सीएलएफ कर्टीब्यूशन एक लाख से अवागत कराया।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने भोजनालय परिसर के आसपास अधिकाधिक वृक्षारोपण सुनिश्चित करने तथा मेनु को स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित रूप से डिस्प्ले करने के निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों एवं आगंतुकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन एवं आजीविका से जुड़े ऐसे प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके।

इस निरीक्षण के दौरान डॉ. पंकज कुमार पांडेय (सचिव लोक निर्माण विभाग, औद्योगिक, खनन एवं आयुष विभाग), जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल, एसएसपी श्वेता चौबे, तपोवन नगर पंचायत अध्यक्ष विनीता बिष्ट, एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिडियाल, डीडीओ मो. असलम, ईओ तपोवन अंजलि, बीडीओ श्रुति वत्स आदि संबंधित उपस्थित रहे।

राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूत करने में संत महापुरुषों की अहम भूमिका-श्रीमहंत रविंद्रपुरी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

महामंडलेश्वर साध्वी भगवती पुरी ने निरंजनी अखाड़े में स्थित कार्तिकेय मंदिर में पूजा अर्चना की विश्व कल्याण की कामना की और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज से आशीर्वाद लिया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने मां मनसा देवी की चुनरी ओढ़कर महामंडलेश्वर साध्वी भगवती पुरी का स्वागत किया। श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि समाज को सांस्कृतिक रूप से एकजुट कर राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूत करने में संत महापुरुषों की अहम भूमिका रही है। महामंडलेश्वर साध्वी भगवती पुरी विद्वान संत हैं और सनातन के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं। सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। महामंडलेश्वर साध्वी भगवती पुरी ने कहा कि संत परंपराओं का पालन करते हुए अखाड़े की उन्नति और समाज को धर्म और अध्यात्म के



मार्ग पर अग्रसर करना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज सनातन परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के साथ मानव कल्याण में भी अहम योगदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर हरिद्वार कुंभ भी भव्य और दिव्य स्वरूप में संपन्न होगा। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रामरतन

गिरी महाराज ने कहा कि महामंडलेश्वर साध्वी भगवती पुरी सनातन के प्रचार प्रसार के साथ मातृशक्ति के कल्याण में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी तेजसानंद गिरी, महंत राज गिरी, महंत सतीश वन, संघ नेता पदम सिंह स्वामी आलोक गिरी व पंडित अधीर कौशिक मौजूद रहे।

नगर निगम हरिद्वार का बंदर पकड़ो अभियान फिर किया शुरू, कनखल क्षेत्र से पकड़े बंदर

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

नगर आयुक्त नंदन कुमार (आईएस) के निर्देशों के क्रम में नगर निगम हरिद्वार द्वारा शहर में बढ़ती बंदरों की समस्या के समाधान हेतु बंदर पकड़ो अभियान एक बार पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। अभियान के तहत गुरुवार को कनखल क्षेत्र में विशेष कार्रवाई करते हुए नगर निगम द्वारा अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से 30 से अधिक बंदरों को पकड़ा गया।

ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष नगर निगम हरिद्वार द्वारा संचालित बंदर पकड़ो अभियान के अंतर्गत 400 से अधिक बंदरों को पकड़ा गया था, जिससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बंदरों के आतंक से आमजन को काफी राहत मिली थी। इसके बावजूद हाल के दिनों में जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निवासियों तथा विभिन्न वार्डों के नागरिकों द्वारा पुनः बंदरों की संख्या बढ़ने एवं उनके द्वारा लोगों को परेशान किए जाने संबंधी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं।

प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त नंदन कुमार द्वारा तत्काल प्रभाव से



अभियान को पुनः संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में कनखल क्षेत्र को प्राथमिकता पर लेते हुए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बंदरों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की गई।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार बंदरों द्वारा राहगीरों, महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को परेशान करने, घरों में घुसकर खाद्य सामग्री नुकसान पहुंचाने तथा धार्मिक स्थलों एवं आवासीय क्षेत्रों में उत्पात मचाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आगामी दिनों में शहर के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी अभियान चलाया जाएगा।

संचालित अभियान के दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा, अतिक्रमण सहायक आदित्य तेश्वर तथा बंदर पकड़ने वाली अनुबंधित एजेंसी के सदस्य उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अभियान को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा तथा बंदरों की समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम हरिद्वार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बंदरों को खाद्य सामग्री उपलब्ध न कराएं तथा बंदरों के जमावड़े वाले क्षेत्रों की सूचना नगर निगम को उपलब्ध कराएं, जिससे आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से की जा सके।

कार्यों की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल का रोका वेतन

पथ प्रवाह, देहरादून।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ जीएमएस रोड स्थित बल्लीवाला फ्लाईओवर से कांवली रोड होते हुए सहारनपुर चौक तक उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा कराए जा रहे अंडरग्राउंड केबल बिछाने के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यों की धीमी प्रगति तथा पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी न लगाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए रोड कटिंग समिति की अनुमति शर्तों का परिपालन करते हुए 05 दिन के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने कार्यों की धीमी प्रगति पर यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कांवली रोड से सहारनपुर चौक तक विभिन्न स्थानों पर सड़क की खुदाई के उपरांत निर्माण सामग्री एवं मलबा अव्यवस्थित रूप से बिखरा हुआ है, जिससे आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है। इस पर उन्होंने यूपीसीएल के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल सड़क किनारे पड़ी निर्माण सामग्री एवं मलबा हटाने के निर्देश



दिए। जिलाधिकारी ने यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यस्थलों पर पर्याप्त संख्या में मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा 500-500 मीटर पैच बनाते हुए प्रत्येक पैच पर कार्यों की गति बढ़ाते हुए आगामी पांच दिनों के भीतर अंडरग्राउंड केबल बिछाने का कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित मार्गों को शीघ्र सड़क पुनर्स्थापन (रोड रिस्टोरेशन) के लिए लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाए, ताकि सड़क मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जा सके। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने यूपीसीएल को प्रतिदिन कार्य प्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि

सभी शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क पुनर्स्थापन एवं मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप ही संपादित किए जाएं, ताकि जनमानस को बेहतर एवं सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने गैल द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु ली गई कार्य अनुमति को शर्तों के अनुरूप पूर्ण करते हुए सड़क लोनिवि को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लोनिवि के अधिकारियों को सड़कों को मानसून से पूर्व ठीक कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने तथा क्षेत्र में यातायात एवं नागरिक सुविधाओं को प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेन्द्र डोभाल, अपर जिलाधिकारी वि/रा के.के. मिश्रा, पुलिस अधीक्षक यातायात लोकेश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, अधि० अभि लोनिवि ओपी सिंह, यूपीसीएल के अधिकारियों सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।



राहुल गांधी का दौरा चढ़ा मौसम की भेंट, जनसभा में पहुंचे समर्थकों के हाथ लगी मायूसी

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का गुरुवार को प्रस्तावित अल्मोड़ा दौरा खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। प्रतिकूल मौसम और उड़ान परिस्थितियों के चलते उनका हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा नहीं पहुंच सका और बीच रास्ते से वापस पंतनगर लौटना पड़ा। इसके चलते जनसभा में राहुल गांधी को सुनने और देखने की उम्मीद लेकर पहुंचे समर्थकों को निराशा हाथ लगी। राहुल गांधी को अल्मोड़ा में परिवर्तन का शंखनाद कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कार्यक्रम की रूपरेखा बदलनी पड़ी। लंबे इंतजार के बाद करीब साढ़े बारह बजे उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंच से घोषणा की कि खराब मौसम के चलते राहुल गांधी अल्मोड़ा नहीं पहुंच सकेंगे। इसके बाद उन्होंने पंतनगर से ही वचुंअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की



आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की

विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई, ईंधन

कीमतों और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं का मनोबल लगातार प्रभावित हो रहा है और राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए राजनीतिक बदलाव जरूरी है। राहुल गांधी ने अल्मोड़ा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए खराब मौसम के कारण नहीं पहुंच पाने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि वह बहुत जल्द अल्मोड़ा आकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। राहुल गांधी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था और पार्टी इसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुमाऊं में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के अवसर के रूप में देख रही थी। कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में अल्मोड़ा पहुंचे थे। हालांकि जनसभा में अपेक्षित भीड़ नहीं जुट सकी और खराब मौसम के कारण राहुल गांधी के नहीं पहुंच पाने से कार्यकर्ताओं का उत्साह भी फीका पड़ गया। राजनीतिक दृष्टि से

महत्वपूर्ण माने जा रहे इस कार्यक्रम से कांग्रेस को जिस जनसंपर्क और राजनीतिक संदेश की उम्मीद थी, वह पूरी तरह आकार नहीं ले सका। राहुल गांधी के वचुंअल संबोधन से कार्यक्रम औपचारिक रूप से जारी रहा, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सुनने और देखने की उम्मीद लेकर पहुंचे कई समर्थक कार्यक्रम स्थल से लौटने लगे। ऐसे में कांग्रेस को इस आयोजन से जिस राजनीतिक बढ़त की उम्मीद थी, वह मौसम की बाधा के चलते पूरी होती नहीं दिखी। इससे पूर्व जनसभा को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक मनोज तिवारी, हरीश धामी, सुमित हृदयेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गविंद सिंह कुजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टट्टा, राजकुमार टुकुराल, प्रकाश जोशी, मदन सिंह बिष्ट, रंजीत रावत, आदेश चौहान, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज सहित तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया।

एक नजर

सेना पर सवाल उठाने वालों को जनता स्वीकार नहीं करेगी: महेश नयाल

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों और राष्ट्रभक्तों की भूमि है, जहां सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति करने वालों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी के अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही खराब मौसम को कारण बता रही हो, लेकिन जनता के बीच अपेक्षित उत्साह दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने पूर्व में सेना के अभियानों पर सवाल उठाकर सैनिकों की भावनाओं को आहत किया है। महेश नयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति को समर्थन देगी तथा प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी।

छत्तीसगढ़ में इबोला की आहट, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

भिलाई। छत्तीसगढ़ में जानलेवा इबोला वायरस की संभावित एंट्री ने स्वास्थ्य महकमे और आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। दुर्ग जिले में इबोला संक्रमण के तीन संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है। इनमें से दो व्यक्ति भिलाई के और एक दुर्ग क्षेत्र का निवासी है। राहत की बात यह है कि प्राथमिक जांच में तीनों की स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियातन कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, भिलाई के रहने वाले दोनों संदिग्ध मरीज हाल ही में अफ्रीकी देश इथियोपिया और युगांडा की यात्रा कर लौटे हैं। वहीं, दुर्ग का रहने वाला तीसरा संदिग्ध व्यक्ति कांगो से भारत आया है, जो छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले कुछ समय तक मुंबई में भी ठहरा हुआ था। इन देशों में इबोला के इतिहास को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्कता बरत रहा है।

21 दिनों का होम आइसोलेशन और निगरानी

जिला स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर तीनों व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक स्वास्थ्य निगरानी (सर्विलांस) शुरू कर दी है। चिकित्सा अधिकारियों के निर्देशानुसार, सभी संदिग्धों को अनिवार्य रूप से 21 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल तीनों की स्वास्थ्य स्थिति पूरी तरह सामान्य है और उनमें इबोला के किसी गंभीर लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी प्रोटोकॉल के तहत उनके स्वास्थ्य पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है।

सीबीएसई की तीन भाषा की नीति पर बवाल, जयराम रमेश बोले

शिक्षा मंत्रालय चला रहा राजनीतिक एजेंडा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को कक्षा 9 और 10 में सीबीएसई द्वारा तीन-भाषा फॉर्मूला लागू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई शैक्षणिक आधार नहीं है और यह पूरी तरह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि दिसंबर 2025 में सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एनसीईआरटी द्वारा विभिन्न भाषाओं की कक्षा-वार पाठ्यपुस्तकें जारी होने तक मौजूदा भाषा व्यवस्था जारी रखी जाएगी। इस फैसले पर उस समय के सीबीएसई अध्यक्ष और सचिव ने भी हस्ताक्षर किए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद मई 2026 में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 और 10 में तीसरी भाषा अनिवार्य रूप से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही स्कूलों को कक्षा 9 के छात्रों को तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताबों का उपयोग करने को कहा गया।

सीबीएसई ने सिफारिशों को किया दरकिनारा

कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि पिछले छह महीनों में ऐसा क्या बदल गया? एनसीईआरटी ने अब तक कक्षा 9 और 10 के लिए तीसरी भाषा की नई पाठ्यपुस्तकें जारी नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने अपनी ही पाठ्यक्रम समिति और गवर्निंग बॉडी की सिफारिशों को दरकिनार कर यू-टर्न लिया है। रमेश ने कहा कि इस फैसले से स्कूलों की शैक्षणिक योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। उनके अनुसार, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई जैसे स्वायत्त संस्थान शिक्षा विशेषज्ञों की सलाह के बजाय सरकार के राजनीतिक एजेंडे के आधार पर काम कर रहे हैं।

कांचुला पुल के पास कार खाई में गिरी; एक की मौत, दो घायल

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

बाढ़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग पर कांचुला पुल के समीप गुरुवार को एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार संख्या यूके-04-2999 अल्मोड़ा से नाचनी की ओर जा रही थी। अपराह करीब दो बजे कांचुला पुल के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे खाई में गिर गया। वाहन में तीन लोग सवार थे। दुर्घटना में



कुंदन सिंह बथ्याल (70) पुत्र महेंद्र बथ्याल निवासी नाचनी, पिथौरागढ़ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गणेश कुमार (32) पुत्र भोपाल राम तथा भूपेंद्र प्रसाद (25) पुत्र दीवानी राम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव कार्य चलाकर दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल अल्मोड़ा भेजा गया। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति दिखाई रचनात्मकता

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला गंगा सुरक्षा समिति और ग्रीन हिल्स ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में अंतर-विद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के 10 विद्यालयों के 73 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जागरूकता और रचनात्मकता का परिचय दिया। कार्यक्रम में बिट्टू कर्नाटक मुख्य अतिथि रहे, जबकि डॉ. दुर्गापाल, उदय किरौला और डॉ. धारा बल्लभ पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पर्वतारोही अनुराग मालू और हर्षित रौतेला ने भी कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। ग्रीन हिल्स ट्रस्ट की मुख्य संयोजक डॉ. वसुधा पंत के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पोस्टर निर्माण और कहानी चित्रण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता की विषयवस्तु 'हमारे भविष्य के लिए प्रकृति एवं जलवायु' रही, जबकि कहानी चित्रण प्रतियोगिता का विषय 'यदि हिमनद बोल सकते'



रखा गया। प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन उदय किरौला, डॉ. धारा बल्लभ पांडे, डॉ. यामिनी कांडपाल और हर्षिता बिष्ट ने किया। पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में मानस पब्लिक स्कूल के दक्षेश जोशी ने प्रथम, पाइनवुड स्कूल की जिआ ने द्वितीय तथा पलक आर्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में रसिका डालाकोटी प्रथम, विवेकानंद इंटर कॉलेज के गौरव सिंह बोर द्वितीय और यामिनी भट्ट तृतीय स्थान पर रहीं। कहानी चित्रण प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में विवेकानंद इंटर कॉलेज की सिद्धि

बिष्ट ने प्रथम, भावना जोशी ने द्वितीय तथा सोनम पिलखाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। वक्ताओं ने छात्र-छात्राओं से हिमालयी पर्यावरण, जल स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजन में ग्रीन हिल्स ट्रस्ट के दीपक जोशी, मनोज गुप्ता, भूषण पांडे, डॉ. दीपा गुप्ता और मीता उपाध्याय सहित अन्य सदस्यों ने सहयोग दिया।

चितई में स्वच्छता अभियान, मंदिर परिसर और आसपास की गई सफाई

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के तहत गुरुवार को विकासखंड हवालबाग की ग्राम पंचायत चितई पंत और चितई तिवारी में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। 'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान के तहत विश्व प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान संचालित किया गया। कार्यक्रम में हरी दत्त पेटशाली इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं, उन्नति स्वायत्त सहकारिता के सदस्यों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा विकासखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर साफ-सफाई की। साथ ही कूड़ा निस्तारण कार्यक्रम भी चलाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र



पंचायत प्रमुख हिमानी कुंडू, जिला पंचायत सदस्य प्रेम सिंह लटवाल, ग्राम प्रधान दीपा आर्या, ग्राम प्रधान धीरज कुमार, सहायक खंड विकास अधिकारी रमेश सिंह कनवाल तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रमोद कुमार पांडे सहित विकासखंड के कई

अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ-सुथरा रखने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।



गन्ना-मूंगफली अंतःफसली खेती प्रणाली से बढ़ेगी किसानों की आय और तिलहन आत्मनिर्भरता: सूर्य प्रताप शाही

पथ प्रवाह, मेरठ।

भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ में गन्ना-मूंगफली अंतःफसली खेती को बढ़ावा देने हेतु किसान-नीति निर्माता-वैज्ञानिक संवाद 'का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री (कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान) सूर्य प्रताप शाही तथा विशिष्ट अतिथि कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा संस्थान के ऑन-स्टेशन प्रक्षेत्र पर गन्ने में मूंगफली अंतः फसलीकरण के अनूठे प्रयोग का सघन भ्रमण कर तथा पौधरोपण करके 'खेत बचाओ अभियान' का संदेश देकर किया गया। इसके उपरांत, कुसावली स्थित आदर्श ऑर्गेनिक फार्म के निकट वृहद किसान-नीति निर्धारक एवं वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने संबोधन में इस नवोन्मेषी कृषि पद्धति की सराहना करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना आधारित कृषि प्रणाली के विविधीकरण तथा किसानों की समृद्धि हेतु यह तकनीक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने विशेष बल देते हुए कहा कि मूंगफली जैसी तिलहनी और अन्य दलहनी फसलों का गन्ना कृषि प्रणाली में समावेश करके देश में तिलहन और दलहन उत्पादन में वृद्धि की अपार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इससे न केवल कृषकों की आर्थिक उन्नति होगी, बल्कि भारत को खाद्य तेलों के आयात पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली लाखों-करोड़ों रुपये (2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक) की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी अभूतपूर्व मदद मिलेगी। मंत्री अपने संबोधन में संस्थान द्वारा किसानों की आजीविका सुदृढ़ करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर किए जा रहे शोध



कार्यों की प्रशंसा की और सभी लाभार्थियों से संस्थान के शोध कार्यों का तुरंत लाभ उठाने की सलाह दी। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने संबोधन में सभी किसानों से मिट्टी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के स्वास्थ्य को उच्च स्तर पर बनाए रखने हेतु प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दी तथा 'खेत बचाओ अभियान' में अपना सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

समेकित कृषि प्रणाली के विविधीकरण को अपनाएं किसान

विशिष्ट अतिथि कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कृषक समुदाय का आह्वान करते हुए कहा कि अब वह समय आ चुका है जब हमारे किसान भाइयों को किसी एक कर्मोडिटी पर निर्भर रहने के बजाय 'समेकित कृषि प्रणाली' के विविधीकरण को अपनाना चाहिए। इस प्रणाली से किसानों की आय सुनिश्चित व सुरक्षित होगी, जनमानस को संतुलित पोषण प्राप्त होगा और तिलहन व दलहन जैसी महत्वपूर्ण कृषि फसलों के उत्पादन में देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर हो सकेगा।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक अमित अग्रवाल ने गन्ना-मूंगफली प्रणाली के

माध्यम से तिलहन आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु कृषि प्रणाली संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं शोध कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

किसानों की बढ़ेगी आय, विदेशी मुद्रा की होगी बचत

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) डॉ. अमरीश कुमार नायक ने तकनीकी पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि गन्ने के साथ मूंगफली एवं दलहनी फसलों के समन्वय से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा स्वास्थ्य तथा संपूर्ण पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन भी सुदृढ़ बना रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्र को खाद्य तेलों के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गन्ना-मूंगफली अंतःफसलीकरण प्रणाली को बहुत व्यापक क्षेत्र में और तीव्र गति से किसानों के बीच ले जाने की महती आवश्यकता है। जहां गन्ने की फसल में दलहनी फसलों के समावेश से किसानों को प्रति हेक्टेयर रु.40000 से लेकर लेकर 750000 तक की वहीं मूंगफली के समावेश से रु. 70000 से लेकर 2100000 प्रति

हेक्टेयर तक की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी।

निदेश डॉ सुनील कुमार ने दी शोध कार्यों की जानकारी

इससे पूर्व, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया तथा संस्थान द्वारा गन्ना फसल प्रणाली के विविधीकरण, किसानों की आय संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में किए जा रहे शोध कार्यों व प्रयासों पर एक विस्तृत तकनीकी व्याख्यान प्रस्तुत किया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के निदेशक डॉ. एस. एन. सुशील ने इस पद्धति को वृहद स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु अपने संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों और तकनीकी प्रसार की रणनीतियों की विस्तृत रूपरेखा साझा की।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की अपार संभावनाएं

अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ एवं मक्का अनुसंधान संस्थान के कंट्री हेड डॉ. महेश गठाला ने इस अवसर पर गन्ना-मूंगफली अंतःफसली पद्धति की सफलता की कहानियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने इस प्रणाली के माध्यम से भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की व्यापक संभावनाओं पर तकनीकी विचार साझा किए। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मोदीपुरम के कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस तकनीक को प्रत्येक किसान के खेत तक पहुंचाने और विशेष प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

किसान के फार्म पर किया स्थलीय निरीक्षण

कार्यक्रम के दौरान समस्त मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों, वैज्ञानिकों तथा नीति निर्धारकों ने कुसावली स्थित 'नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्म' के निदेशक विनोद सैनी के

प्रक्षेत्र का दौरा किया। यहाँ गन्ने के साथ अंतःफसली के रूप में वैज्ञानिक पद्धति से लगी हुई मूंगफली की फसल का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। अतिथियों ने प्रक्षेत्र पर ही उपस्थित प्रगतिशील किसानों के साथ इस पद्धति के व्यावहारिक लाभों और भविष्य की संभावनाओं पर अत्यंत व्यापक एवं जीवंत विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की 15 से अधिक जिलों के 600 से अधिक किसानों, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के अधिकारियों, आसपास के आठ जिलों से चीनी मिलों के प्रबंधकों, ग्राउंड स्टाफ, मेरठ कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, नाबार्ड के अधिकारियों, अग्रणी किसानों एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

ये रहे कार्यक्रम में उपस्थित

इस भव्य कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. अमृतलाल मीणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य परियोजना अधिकारी डॉ. रघुवीर सिंह ने देश-विदेश से पधारे सभी अतिथियों, वैज्ञानिकों, मीडियाकर्तियों एवं कृषक भाइयों का कार्यक्रम को सफल बनाने में अमूल्य सहभागिता हेतु विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉ. एन. रवि शंकर, डॉ. आर पी मिश्र, डॉ. ललित कुमार, डॉ. टी. पी. स्वर्णम, डॉ. पीयूष पुनिया, डॉ. फूलचंद जाट, डॉ. चंद्रभानु, डॉ. आशीष कुमार प्रुष्टि, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. जगन सिंह गोरा, डॉ. मोहम्मद आरिफ, डॉ. कमलेश कुमार, डॉ. प्रमोद कुमार सहित संस्थान के अनेक अधिकारी, शोधकर्ता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक नजर

पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने किया हंगामा, कार्यालय में जड़ा ताला



पथ प्रवाह, हरिद्वार। पथ प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं किए जाने पर कांग्रेस पार्षद सोहित सेठी और हिमांशु गुप्ता ने समर्थकों के साथ नगर निगम पहुंचकर पथ प्रकाश विभाग कार्यालय पर तालाबंदी कर विरोध जताया। वार्ड 8 के पार्षद पार्षद सोहित सेठी ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे काफी समय से खराब स्ट्रीट लाइट बदलने की मांग कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट खराब होने की वजह से क्षेत्र में अंधेरा पसरा रहता है। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे हैं। जिसे सहन नहीं किया जाएगा। गऊघाट क्षेत्र के पार्षद हिमांशु गुप्ता ने स्ट्रीट लाइट बंद होने का हवाला देते हुए कहा कि यात्री बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जबकतरे और भिखारी अंधेरे का फायदा उठाकर चोरियां करते हैं। अंधेरे के कारण वाहन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनहित के कार्यों में भी भेदभाव की नीति अपनायी जा रही है। जनसमस्याओं के समाधान पर कोई अमल नहीं होता है। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कैश खुराना और पार्षद विवेक भूषण विक्की ने कहा कि जनहित की समस्याओं का संज्ञान लेना चाहिए। सभी वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत बदल जाए पथ प्रकाश व्यवस्था सुचारू की जाए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुरली मनोहर ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी बिना भेदभाव के समान रूप से समस्याओं का समाधान करें। पार्षद महावीर वशिष्ठ, पूर्व पार्षद राजीव भार्गव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और विभागीय अधिकारियों की मनमानी पर नाराजगी जतायी। एसएनए श्यामसुंदर के समस्या के समाधान का आश्वासन देने पर हंगामा कर रहे पार्षद और कार्यकर्ता शांत हुए।

पतंजलि विश्वविद्यालय तथा इण्डोनेशिया की यूनिवर्सिटी हिंदू नेगरी के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर

पथ प्रवाह, हरिद्वार/इण्डोनेशिया। पतंजलि विश्वविद्यालय तथा इण्डोनेशिया के एकमात्र हिन्दू विश्वविद्यालय Universitas Hindu Negeri (UHN) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MOU) हुआ। इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण स्वयं उपस्थित रहे। इण्डोनेशिया का शिक्षा जगत तथा सनातन के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग इस MOU के साक्षी बने तथा उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को कवर कर प्रचारित-प्रसारित किया। इस अवसर पर बाली के MLA डॉ. सोमवीर जो भारतीय परंपरा के एकमात्र विधायक हैं भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर आचार्य जी ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन के तहत विद्यार्थियों का स्ट्रेट सेशन के साथ-साथ अनुसंधान और योग प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता हेतु साझा मंच मिलेगा। साथ ही दोनों देशों के विद्यार्थी एक-दूसरे से अनुसंधान कार्य साझा कर अपना ज्ञानवर्धन



कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इण्डोनेशिया का यह विश्वविद्यालय विविध 35 संकाय (Faculty) संचालित करता है। आचार्य जी ने कहा कि यहाँ आकर हम अभिभूत हैं और बहुत जल्द शैक्षणिक क्षेत्र के साथ-साथ योग और सनातन को इण्डोनेशिया में पुनर्स्थापित करने के क्षेत्र में पतंजलि बहुत बड़ा कार्य करेगा।

कार्यक्रम में HN के Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana ने कहा कि योग-आयुर्वेद के क्षेत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय

एक अग्रणी संस्थान है तथा इसकी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा है। उन्होंने कहा कि इस MOU के माध्यम से योग, आयुर्वेद के साथ-साथ अन्य विषयों जैसे कृषि, अनुसंधान, सूचना एवं तकनीक आदि में भी इण्डोनेशिया के विद्यार्थियों लाभ उठा सकेंगे। Prof. Made Purnama Uhn ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ हुआ यह एमओयू इण्डोनेशिया के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णम अवसर है जिसका लाभ पूरे इण्डोनेशिया को मिलेगा।

इससे पूर्व Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana तथा Prof. Made Purnama Uhn की अगुवाई में Universitas Hindu Negeri (UHN) की प्रबंधन समिति के सदस्यों ने पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice-Chancellor) एवं पतंजलि विश्वविद्यालय की पूरी टीम का भावपूर्ण स्वागत किया।

संस्कारयुक्त शिक्षा ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार-स्वामी ज्ञानानंद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। श्रवण सेवा शोध संस्थान एवं अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सेवा समूह के संयुक्त तत्वावधान में श्रीकृष्ण कृपा धाम भीमगोडा में सम्मान समारोह का आयोजन कर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने मेधावी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कारयुक्त शिक्षा ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार बनती है और उन्हें समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने योग्य बनाती है। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता शिल्पी गिरि ने किया। संस्थान की ओर से प्रगति गुप्ता, लक्ष्मी शर्मा, आदित्य गिरि, पल्लवी गिरि, सिद्धार्थ, हर्ष, अभिनव, कनिका, तान्या, पारस, अमन, कशिश एवं प्रियांशु सहित कई मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रवण सेवा शोध संस्थान के संस्थापक डा.अशोक



गिरि, प्रमोद गिरि, सोमदत्त गिरि, रजकुमार विज, शत्रुघ्न गिरि, हरिशंकर गिरि, सुशील शर्मा, पवन कुमार, श्रीधर गिरि, डा.विवेक कोली, अजय मलिक, शैलेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।



विश्व पर्यावरण दिवस: कुंभ नगरी में चलेगा 'हरित हरिद्वार' अभियान, बड़े पैमाने पर होगा वृक्षारोपण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

आगामी कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के अंतर्गत हरिद्वार को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से मेला प्रशासन द्वारा संचालित 'हरित हरिद्वार' अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कुंभ नगरी में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेलाधिकारी सोनिका की पहल पर मेला अधिष्ठान, जिला प्रशासन तथा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अभियान में विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

अभियान के अंतर्गत शहर की प्रमुख सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, घाटों के आसपास के क्षेत्रों तथा कुंभ मेला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न परिसरों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। इसके साथ ही जन सहयोग से लगाए जाने वाले पौधों के संरक्षण एवं नियमित



देखभाल के लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है, जिससे यह पहल दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बन सके।

मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि पर्यावरण

संरक्षण वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आवश्यकताओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए

वृक्षारोपण एवं हरित विकास को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी भी है। ऐसे में इसके प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने नागरिकों से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कम से कम एक पौधा लगाने एवं उसके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण तभी सार्थक होगा जब लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने युवाओं, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा इसे जनभागीदारी का अभियान बनाने की अपील की। मेलाधिकारी सोनिका ने बताया कि कुंभ मेला-2027 की तैयारियों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण तथा हरित अवसंरचना के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में 'हरित हरिद्वार'

अभियान को दीर्घकालिक स्वरूप दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरणीय जागरूकता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे विशाल आयोजन को पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए हरित क्षेत्रों का विस्तार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा जनसहभागिता आधारित प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। 'हरित हरिद्वार' अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आगामी कुंभ मेले को अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

उल्लेखनीय है कि मेला प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा पिछले कुछ समय से शहर में स्वच्छता अभियान, हरित पट्टियों के विकास, पार्कों के सौंदर्यीकरण, पौधरोपण कार्यक्रमों तथा पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इन प्रयासों को नागरिकों का व्यापक सहयोग प्राप्त हो रहा है।

एक नजर

अदालत मामलों के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें मुकदमों की तय समय में निपटारे के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने एक वकील की इस अर्जी को खारिज कर दिया। याचिका में देशभर की अदालतों में बार-बार मिलने वाली तारीखों (स्थगन) को रोकने के लिए कड़े और एक समान नियम बनाने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता ने सभी अदालतों के लिए एक नेशनल केस फ्लो मैनेजमेंट पॉलिसी लागू करने की मांग भी की थी। इसमें मुकदमों के हर चरण के लिए समय सीमा तय करने, जरूरत पड़ने पर रोजाना सुनवाई करने और पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटारने का सुझाव दिया गया था। सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस मामले को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और विभिन्न बार एसोसिएशनों के पास जाएं। अदालत ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि वे वकीलों से दुश्मनी नहीं लेना चाहते क्योंकि हम वकीलों के दोस्त हैं।

मिशन 2029: केंद्र सरकार का बड़ा दांव

चुनाव से पहले परिसीमन की तैयारी; क्षेत्रीय दलों से भी मंथन शुरू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से लंबित परिसीमन विधेयक को फिर से धरातल पर उतारने की सक्रिय कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा करना है।

क्षेत्रीय क्षत्रणों को साधने की कवायद

इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर सरकार किसी भी टकराव से बचना चाहती है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे आम सहमति बनाने का दौर शुरू हो चुका है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। इन चर्चाओं में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और अन्य क्षेत्रीय हितधारक शामिल हैं। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य संसदीय प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर क्षेत्रीय दलों की चिंताओं को दूर करना है।

टकराव नहीं, आम सहमति पर जोर

परिसीमन का सीधा मतलब जनसांख्यिकीय बदलावों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना है। बीते कुछ वर्षों में कई राज्यों ने इस बात पर चिंता जताई है कि नई व्यवस्था से संसद में उनका प्रतिनिधित्व बदल सकता है। इस राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी प्रमुख दलों के बीच एक साझा ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसे संसद में पेश नहीं किया जाएगा। विधेयक को पेश करने का समय पूरी तरह से जारी बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा।

एक देश, एक चुनाव की तैयारी

चुनावी सुधारों की यह कड़ियां केवल परिसीमन तक ही सीमित नहीं हैं। केंद्र सरकार इसके साथ ही एक देश, एक चुनाव यानी देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर भी आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ हो रही बैठकों में इन दोनों ही बड़े मुद्दों को मेज पर रखा गया है। अगर सरकार इस मोर्चे पर राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहती है, तो अगले आम चुनाव से पहले देश के चुनावी प्रतिनिधित्व की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि, फिलहाल बातचीत का दौर जारी है और अंतिम फैसला होना बाकी है।

अपनी नाकामियां छिपा रही है सरकार

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दों पर विफल रही है और अपनी नाकामियों को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण आंकड़ों को छिपा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए खरगे ने कहा कि एनएफएचएस-6 के आंकड़ों ने भाजपा सरकार की पूर्ण अक्षमता को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि देश में हर पांच में से एक बच्चा गंभीर कुपोषण का शिकार है, जबकि एक-तिहाई बच्चे कम वजन के हैं। इसके अलावा 6 से 23 महीने की उम्र के 84 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है।

दो दिनों में 4500 टन कूड़े का निस्तारण, अभियान को दिया गया विस्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद में इन दिनों स्वच्छता को लेकर अभूतपूर्व जागरूकता देखने को मिल रही है। शहर के बाड़ों से लेकर ग्राम पंचायतों, पीठ बाजार, मंडी परिषद, स्टेट हाईवे एवं नेशनल हाईवे तक हर स्थान पर साफ-सफाई का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान ने जनपद की तस्वीर बदलने का कार्य किया है।

इस अभियान के अंतर्गत नियमित रूप से साफ-सफाई, कूड़ा उठान एवं निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं साप्ताहिक रूप से स्वच्छता कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ी है और कार्यों में तेजी आई है। मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से यह अभियान और अधिक सुदृढ़



रूप में संचालित हो रहा है। जनपदवासियों द्वारा भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अभियान के तहत मात्र दो दिनों में

लगभग 4500 टन कूड़े का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर काफी बेहतर हुआ है और एक स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण का निर्माण हो रहा है।

बहादुराबाद बाईपास से जगजीतपुर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर

कार्यों की प्रगति का डीएम ने किया निरीक्षण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

आगामी कांवड़ यात्रा एवं कुंभ मेले के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रिंग रोड के अंतर्गत बहादुराबाद बाईपास से जगजीतपुर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्था एवं संबंधित कांटेक्टरों को निर्देशित किया कि 30 जून तक पूर्ण किए जा सकने वाले सभी कार्यों को त्वरित गति एवं उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ मेले के दौरान किसी भी प्रकार के सड़क निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे, अतः पूर्व निर्धारित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने हेतु श्रमिकों की



संख्या बढ़ाने तथा मिट्टी ढुलाई के लिए डंपरों की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने फ्लाईओवर मार्ग में आने वाली भूमि, वृक्ष कटान एवं अन्य बाधाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कांटेक्टरों को

आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मेला अधिकारी/एसएलओ आकाश जोशी, प्रोजेक्ट निदेशक एनएचआई विशाल गोयल, कांटेक्टर नरेश मंगला, सालवान सिंह गुलेरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती-जाती रहती है

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नागपुर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की कथित आत्महत्या की घटना को लेकर गुरुवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी की कीमत पूरी एक युवा पीढ़ी चुका रही है। उन्होंने दावा किया कि छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि मोदी

जी की एक भ्रष्ट, टूटी हुई व्यवस्था की देन है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपये का कर्ज लिया। नागपुर में खुद रसोइये की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहां कोचिंग कर सके। उन्होंने कहा, एक पिता

जो कर सकता था, उसने सब किया। फिर नीट पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही समिति। वही तबादला। वही जांच। न सुधार, न न्याय। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती-जाती रहती है।